

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां,  
उत्तराखण्ड।

**सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1 देहरादून दिनांक 17 फरवरी, 2010**  
**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2009-10 में जिला योजना (सामान्य) पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान हेतु अनुपूरक मांग से बजट प्राविधन के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-7858/नियो0/जिला योजना/2009-10 दिनांक 17 जनवरी, 2010, पत्र संख्या:-7252/नियो0/जिला योजना/2009-10 दिनांक 02 जनवरी, 2010 एवं शासनदेश संख्या:-706/XIV-1/2009, दिनांक 17 अगस्त, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित जिला योजना (सामान्य) हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अतिरिक्त प्रश्नगत योजना हेतु रुपये 41,11,000/- (रु0 इक्तालीस लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि जिसका जनपदवार विवरण संलग्न है, व्यय करने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के तहत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।
- (2) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- (4) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(2)

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।

(6) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या -18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनागत-107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 91-सहकारी ऋण योजना-9101-पैक्स सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर को अनुदान की मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-38/XXVII-1/2010 दिनांक 19 जनवरी, 2010 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
अपर सचिव।

संख्या:-248/XIV-1/2010-5(10)/2009, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री सहकारिता, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल, /कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या:- 278/XIV-1/2010-5(10)/2009, दिनांक 17 फरवरी, 2010 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु जनपदों से प्राप्त जिला योजना के आधार पर जिला योजना हेतु निर्धारित / उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु लेखाशीर्षवार धनराशि आवंटन का विवरण।

योजना/यद का नाम	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	फिरोज़गढ़	चम्पावत	देहरादून	पौड़ी	टिहरी	धमौली	रूद्रप्रयाग	उत्तरकाशी	योग
2425- सहकारिता-आयोजनागत 107- कैडिट सहकारी समितियों को सहायता 91- सहो ऋण योजना, 9101- पैक्स के सदस्यों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान												
20- सहायक अनुदान/अनुदान/ राज सहायता योग:-	0.99	4.95	0.53	6.14	3.64	1.47	7.02	2.15	4.16	3.36	6.70	41.11
	0.99	4.95	0.53	6.14	3.64	1.47	7.02	2.15	4.16	3.36	6.70	41.11

(अभिमत सिंह नेगी)  
अपर सचिव।